

दैनिक रोकठोक लेखनी^R

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

→ कोशयारी की जगह रमेश बैस बने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल

राष्ट्रपति ने 13 राज्यों में की नई नियुक्तियां...



नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके

अलावा महामहिम राष्ट्रपति ने कुछ और भी नियुक्तियां की हैं। पूर्व वित्त राज्यमंत्री मंत्री शिवप्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो राजस्थान के कदावर नेता गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल फागु चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है।

बोरीवली में रिश्ते तार-तार
भाई और मामा ने नाबालिंग लड़की की आबरू लूटी, दोनों गिरफ्तार



मुंबई : मुंबई में रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिंग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लड़की के करीबी रिशेदार हैं। पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही दोनों पर एक्शन लिया गया है।

भाई और मामा ने कई बार किया दुष्कर्म

बोरीवली में मौसी के घर रह रही 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसके मौसेरे

भाई और मामा ने ही कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की ने इस घटना की जानकारी विवार में अपने चाचा को दी, जिसके बाद उहोंने विवार पुलिस से शिकायत की। पुलिस को जानकारी मिलते ही मामला मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया और तेजी से कार्रवाई की गई।

चार घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जानकारी मिलते ही तेजी से कार्रवाई की। सूचना मिलने के चार घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामा की उम्र 50 वर्ष और भाई की 19 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने POCSO अधिनियम और भारतीय डंड संहिता (IPC) की धारा 376, 376 (2), 376 (2) (1) के तहत भी मामला दर्ज किया है।

→ 200 सीटों का लक्ष्य, गद्दार नहीं खुदार है हम...

BJP की नासिक बैठक में महाविजय अभियान 2024 का उद्घोष

मुंबई: महाराष्ट्र बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने महाविजय अभियान 2024 की घोषणा की है। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और हमने टी-20 मैच की शुरूआत कर दी है। हमारी बैटिंग जारी है और वर्ष 2024 के चुनाव में जीत मिलने के बाद ही हम बैटिंग खत्म करेंगे। हम सब मिलकर महाविजय अभियान को सही तरीके से आगे बढ़ायेंगे। उहोंने कहा कि हमें पांच साल का काम ढाई साल में करना है। नासिक में प्रदेश कार्यकारिणी के दूसरे व अंतिम दिन फडणवीस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को उद्धृत करते हुए कहा कि बीजेपी का मंत्र सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है।



'6 महीनों में किसानों को 10000 करोड़ दिए'

फडणवीस ने कहा कि पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम व्यक्ति की बेहतरी के लिए अंत्योदय का विचार दिया। अंत्योदय का विचार सही अर्थों में लागू करने का काम प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी ने कर दिखाया। फडणवीस ने कहा कि 6 माह में हमने किसानों को 10,000 करोड़ रुपये की मदद की है।

जो काम महाविकास आघाडी सरकार ने कबूल किए थे, वे हम कर रहे हैं।

यह गद्दारों की नहीं, खुदारों की सरकार

फडणवीस ने कहा कि यह गद्दारों की नहीं, खुदारों की सरकार है। पहले वाली सरकार गद्दारों की थी। ठाकरे की तरफ इशारा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कह रहे हैं कि विधायिकों की अयोग्यता मामले में फैसला उनके पक्ष में आएगा। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं ताकि जो चार-छह लोग उनके पास बचे हैं, वे उनका साथ न छोड़ें। फडणवीस ने कहा कि हम सभी को जनता के बारे में सोचना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा, इस पर विचार त्याग देना चाहिए। हमने महाविजय अभियान हाथ में लिया है। हमारी सरकार हिंदुत्व के विचारों के लिए बनी है।

संपादकीय / लेख



पेंशन की फाँस

पिछले दिनों गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करके जो राजनीतिक ब्रह्मस्त्र चलाया है, उससे केंद्र की भाजपा सरकार सांसद में है। आर्थिक सुधारों व वित्तीय संतुलन की कवायद के बीच पुरानी पेंशन के देशव्यापी बोझ से अर्थव्यवस्था के दबाव में आने की

फैसल शेख (प्रधान संपादक)

आशंका जाने-माने अर्थशास्त्री जता रहे हैं। पिछले दिनों हिमाचल के चुनाव में ओल्ड पेंशन बड़ा सियासी मुद्दा बना, भाजपा ने उसकी कीमत भी चुकाई। बताते हैं कि पेंशन योजना लागू होने से राज्य पर नई पेंशन के मुकाबले चार गुना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसे में पहले ही कर्ज में दूबी सरकारें वित्तीय सुशासन स्थापित कर पाएंगी, इस बात में संदेह है। वहीं केंद्र की तरफ से कोई वित्तीय सहयोग की बात नहीं कही गई है। पिछले दिनों कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल व पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। दरअसल, 18 साल पहले पुरानी पेंशन योजना को बदलकर नई पेंशन योजना को लागू किया गया। पुरानी पेंशन का निर्धारण मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होता था। जबकि नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारी के वेतन से कटे गये अंश से ही पेंशन दी जाती है। उसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है और सेवा अवधि कम होने पर यह थोड़ी रह जाती है। कर्मियों के वेतन से कटे पैसे का पचासी फीसदी सरकारी प्रतिभूतियों तथा बाकी पंद्रह फीसदी खुले बाजार में निवेश किया जाता है, जिसकी आय से कर्मियों को पेंशन का भुगतान होता है। निस्संदेह, जीवन भर नौकरी के जरिये सेवा करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापे के लिये आर्थिक संरक्षण जरूरी है। ये लोककल्याणकारी सरकारों का दायित्व भी होता है। लेकिन लोककल्याण का मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देश की हालत श्रीलंका व पाकिस्तान जैसी हो जाए। इस योजना से कर्मचारियों में उत्साह है और अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठन इसे लागू करवाने के लिये दबाव बना रहे हैं। चिंता जताई जा रही है कि कहीं ये मुद्दा अगले आम चुनाव में भाजपा के लिये मुश्किलें पैदा न कर दे।

वहीं दूसरी ओर देश के कई जाने-माने अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोटेक सिंह अहलूवालिया ओल्ड पेंशन योजना को अव्यावहारिक व भविष्य में आर्थिक कंगाली लाने वाला बता चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि इसका परिणाम यह होगा कि दस साल बाद वित्तीय अराजकता पैदा हो जाएगी। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर नये सिरे से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे अहलूवालिया नब्बे के दशक के बाद के तीन दशकों में देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से गहरे तक जुड़े रहे हैं। वे लुभावनी राजनीति करने वाले नेताओं को चेता चुके हैं कि एक अर्थशास्त्री के नाते मैं कहुंगा वे ऐसे कदम उठाने से बचें जो भविष्य में वित्तीय तबाही के कारक बन सकते हैं। दरअसल, अर्थशास्त्री मानते हैं कि देश की जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि इस फैसले की भविष्य में हमें कीमत चुकानी पड़ेगी और विकास के हिस्से का धन गैर-उत्पादक कार्यों में खर्च होगा। कर्मचारियों को तो इसका लाभ होगा, लेकिन देश का बड़ा तबका उसकी कीमत चुकाएगा।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुंबई- ठाणे समाचार

2

कर्ज के चलते परिवार हुआ खत्म!

युवक ने पत्नी को मार की आत्महत्या



पत्रकार शशिकांत के परिवार को 25 लाख की मदद...

बेटे को पक्की नौकरी देगी महाराष्ट्र सरकार



महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में रल गिरी रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ आवाज उठाने वाले खोजी पत्रकार शशिकांत वारिसे की कथित हत्या का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। एक तरफ महाविकास आघाडी शिंदे-फडणीवीस सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर पत्रकार संगठन मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कई प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है। रल गिरी जिले के राजापूर के पत्रकार शशिकांत वारिसे की संदिग्ध मौत के मामले में उपमुख्यमंत्री से

देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को एसआईटी जांच (रक्छ) का आदेश दिया। इस बीच अब राज्य सरकार ने वारिसे के परिवार को सरकार को और से मदद मिलनी चाहिए। पत्रकारों की इस मांग का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय सामंत ने तत्काल मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की। इसके बाद सामंत ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपये व अन्य माध्यम से 15 लाख रुपये यानी कुल 25 लाख रुपये मृतक पत्रकार के परिवार को देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने वारिसे के बेटे को पक्की नौकरी देने का वादा भी किया।

बात करते हुए मंत्री उदय सामंत ने आश्वासन दिया कि शशिकांत वारिसे के बेटे यश को भी पक्की नौकरी दी जाएगी। हालांकि दिवंगत पत्रकार का बेटा यश अभी पढ़ाई कर रहा है।

महानगरी टाइम्स के साथ काम करने वाले मराठी पत्रकार शशिकांत वारिसे की अचानक मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। पत्रकार संगठनों ने मांग की थी कि पीड़ित परिवार को सरकार को और से मदद मिलनी चाहिए। पत्रकारों की इस मांग का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय सामंत ने तत्काल मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की। इसके बाद सामंत ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपये व अन्य माध्यम से 15 लाख रुपये यानी कुल 25 लाख रुपये मृतक पत्रकार के परिवार को देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने वारिसे के बेटे को पक्की नौकरी देने का वादा भी किया।

आयकर अधिकारी बन 'स्पेशल 26' जैसी लूट को दिया था अंजाम

कोर्ट ने नौ लोगों को सुनाई सजा



मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने फिल्म स्पेशल-26 की तरह आयकर अधिकारी बन एक व्यवसायी के घर से लूट मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है। इन लोगों ने व्यवसायी के घर से 1.65 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। कोर्ट ने छह दोषियों को 10 साल कैद और तीन को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को डकैती, अवैध रूप से प्रवेश और अपहरण की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। मामला, 2015 का है। व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, घटना से 20

दिन पहले उसका एक परिचित उसके घर आया और उसे कुछ दिनों के लिए रखने के लिए दो बैग दिया। चूंकि, पीड़ित व्यवसायी के उससे अच्छे संबंध थे, ऐसे में उसने बैग घर पर रख लिए और उन्हें एक अलमारी में बंद कर दिया। व्यवसायी के मुताबिक, इस बात की जानकारी सिर्फ उसकी पत्नी को थी। व्यवसायी ने बताया, दो जून, 2015 को उसके घर में कुछ लोग आए और अपना परिचय आयकर अधिकारियों के रूप में दिया। इस दौरान उन लोगों ने व्यवसायी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और दोनों बैग से 40 लाख रुपये के आभूषण, 1 करोड़ रुपये नकद थे बरामद किए। इस दौरान 25 लाख रुपये के कलाई घड़ियां भी घर से मिलीं।

शिकायत में व्यवसायी ने बताया कि कथित अधिकारियों ने उसके परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया।

सेक्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़!

24 वर्षीय युवती चला रही थी देह व्यापार, हुई गिरफ्तार



ठाणे : ठाणे में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 24 वर्षीय एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कलवा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि युवती मुंबई के अंधेरी की रहने वाली है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को एक नकली ग्राहक द्वारा देह व्यापार की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद कलवा नाका से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया।



8 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस ने चार घंटे में आरोपियों को दबोचा



मुंबई : विरार = पूर्व रहने वाली एक युवती से बलात्कार के मामले में एमएचबी पुलिस ने एक ५० वर्षीय शख्स और उसके एक बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि दिव्यांग होने के कारण दूसरे आरोपी बेटे को जांच एवं कानूनी कार्रवाई में मदद करने की नोटिस दी है। सभी आरोपी पीड़ितों के रिशेदोर बताए जा रहे हैं। बलात्कार का यह मामला ८ साल पुराना है। उस समय पीड़ितों की उप्र महज १४ साल थी इसलिए पुलिस ने एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ पोक्सों की धाराएं भी लगाई हैं। बता दें कि विरार -पूर्व में रहने वाली पीड़ितों कुछ पारिवारिक कारणों से वर्ष २०१४ में बोरीवली -पश्चिम स्थित एमएचबी

मुंबई निकाय चुनाव में भाजपा रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी : बावनकुले



मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रेश्वर बावनकुले ने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी मुंबई निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। मुंबई निकाय चुनाव पिछले साल की शुरूआत से देव हैं भाजपा की मुंबई इकाई की कार्यकारी समिति को संवोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई भाजपा के अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार के नेतृत्व के कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में रिकॉर्ड जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने दावा किया, 'मुंबई में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को कम से कम 2,000 घरों में जाना चाहिए और पार्टी की पहुंच बढ़ानी चाहिए। यह अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है क्योंकि हमारी ऐसी सरकारें हैं जो केंद्र के साथ-साथ राज्य में भी अच्छे और तरित निर्णय लेती हैं।' शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए बावनकुले ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शायद राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई।

35 के बाद माँ बनना हो रहा जानलेवा

कोविड के बाद मुंबई में ये आंकड़े डरा देने वाले



मुंबई: गर्भावस्था और कोरोना संक्रमण के कारण मुंबई में मातृ मृत्यु दर भले ही कम हो रही हो, लेकिन 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में माँ बनने का जोखिम बढ़ रहा है। 2018 में 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में मातृ मृत्यु दर जहां 18 थी, वहीं 2022 में बढ़कर यह 29 हो गई। इसे नियत्रित करने के लिए विशेषज्ञों ने 'प्लान प्रेग्नेंसी' का सुझाव दिया है। प्लान प्रेग्नेंसी के जरिये जहां मातृ मृत्यु को नियत्रित किया जा सकता है, वहीं प्रेग्नेंसी भी सफल हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण (सेप्सिस), रक्तस्राव, टीबी आदि के चलते मुंबई में मातृ मृत्यु दर अधिक थी। पिछले कुछ वर्षों में यह कम हुई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पांच साल पहले मुंबई में हर वर्ष औसत 218 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु होती थी, लेकिन बीते वर्ष यह संख्या घटकर 193 रह गई है।

गर्भावस्था के दौरान संक्रमण (सेप्सिस), रक्तस्राव, टीबी आदि के चलते मुंबई में मातृ मृत्यु दर अधिक थी। पिछले कुछ वर्षों में यह कम हुई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहां जागरूकता बढ़ी है और इस कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।

मुंबई में 20 से 35 वर्ष की उम्र में महिलाएं गर्भधारण करना पसंद करती थीं। 19 से 25 वर्ष की आयु में गर्भधारण को प्राथमिकता दी जा रही है। 19 से



महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के इस्तीफे का राकांपा, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने स्वागत किया



मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने का स्वागत किया है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कोश्यारी के हटने से महाराष्ट्र अब राहत महसूस कर रहा है, लेकिन कोश्यारी को पद से हटने का फैसला केंद्र को बहुत पहले लेना चाहिए था।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय रात ने भी कोश्यारी को पद से हटने के फैसले का स्वागत करते हुए इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। वहीं, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटेल ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अब यह पता चलेगा कि काफी देरी के बाद कोश्यारी को

हटाने का फैसला उसके लिए आगामी चुनावों में कितना महंगा साबित होगा।

राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञिति में रविवार को बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा पद्म ने कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी पर अपनी टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए कोश्यारी ने पिछले महीने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी को पद छोड़ने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है और वह अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने तथा अन्य गतिविधियों में बिताना चाहते हैं।

कोश्यारी (80) ने सितंबर 2019 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उस समय पदभार संभाला था, जब राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से अपना नामा तोड़ लिया था। उन्होंने देवेंद्र

विश्वविद्यालय के पास सोमैया की पीएचडी का कोई प्रमाण नहीं



मुंबई : भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया अपनी (फर्जी) डॉक्टरेट डिग्री के कारण एक बार फिर सुधियों में आ गए हैं। खुलासा हुआ है कि मुंबई विश्वविद्यालय के पास सोमैया की पीएचडी का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सबूत के तौर पर सोमैया द्वारा दिए गए कागजहाँ को ही सबूत मानकर आगे सरकाने का मामला सामने आया है। सूचना अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से मुंबई विश्वविद्यालय की पोल खोली गई है। किरीट सोमैया की पीएचडी संदिग्ध है इसलिए सांताकुर्ज की किरण फाटक ने सूचना का अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी थी। विश्वविद्यालय ने २४ जनवरी, २०२३ को फाटक को भेजे पत्र में जो जानकारी दी है, वह दिशाभूल करनेवाली है क्योंकि २७ दिसंबर, २०२२ को जो दस्तावेज किरीट सोमैया ने विश्वविद्यालय को दिए थे, वही दस्तावेज विश्वविद्यालय ने फाटक को फॉरवर्ड ह कर दिए।

युवासेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से विश्वविद्यालय के फर्जी होने की शिकायत की है। विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद के पूर्व सदस्य प्रदीप सावंत और राजन कोलंबेकर ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में उनका कहना है कि जब विश्वविद्यालय के कम-से-कम तीन विभागों को यह जानकारी

होनी चाहिए तो प्रशासन पदवीधर से दस्तावेज मांग रहा है। यह तो एक अपराधी से सबूत मांगने जैसा है। डिमांड थीसिस में मुख्य दस्तावेज के १,१७० पृष्ठ सॉफ्टकॉपी द्वारा प्रदान किए गए हैं (वास्तव में २००५ में बहुत संभव नहीं है)। इसके अलावा विश्वविद्यालय से अन्य दस्तावेजों का न मिलना भी संदिग्ध है, इस प्रकार इस आरोप की पुष्टि होती है कि सोमैया की डॉक्टरेट डिग्री फर्जी है। प्रदीप सावंत और राजन कोलंबेकर ने राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।

सोमैया की पीएचडी डिग्री फर्जी होने का शक होने के बाद पत्राचार के माध्यम से विश्वविद्यालय के फर्जी कामकाज का खुलासा हुआ है। किरण फाटक को भेजे पत्र पर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. इस पर संगीता पवार के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।



राजद पवार ने केंद्र पर साधा निशाना

फडणवीस के दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करेंगी महिलाएं

महाराष्ट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने फलों और सब्जियों के निर्यात में बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए केंद्र की नेंद्र मोर्डी सरकार की आलोचना की है। वह शनिवार को नवी मुंबई के सानापाड़ा में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात कर रहे थे।

पवार ने कहा, केंद्र फलों और सब्जियों के निर्यात में आने वाले मुद्रों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो किसानों, विशेष रूप से व्याज उगाने वालों को परेशान कर रहा था, एक ऐसी फसल जिसे घेरलू स्तर पर अच्छी कीमत पाने के लिए निर्यात करने की आवश्यकता है। उन्होंने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे, रेल मार्गों और हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में वृद्धि का भी जिक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इन सभी ने कृषि



क्षेत्र पर भी भार डाला है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र को कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इसके निर्यात में बाधाएं हैं, जिन पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है।

कोश्यारी को बहुत पहले हटा देना चाहिए था: शरद पवार

शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जाने से महाराष्ट्र राहत में है, लेकिन केंद्र द्वारा यह फैसला है कि कोश्यारी को बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। अपने इतिहास में महाराष्ट्र ने राज्यपाल के पद पर कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। मैं केंद्र सरकार के फैसले से प्रसन्न हूं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मने कोश्यारी

उन्होंने मांग की कि कोश्यारी ने अगर कोई असंवैधानिक फैसले लिए हैं तो उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने नागपुर में पत्रकर्तों से कहा कि महाराष्ट्र अब राहत में है। यह बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसे काफी पहले ले लिया जाना चाहिए था। अपने इतिहास में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले फडणवीस के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य मानदेय जारी करने की मांग को लेकर एक सप्ताह से फडणवीस के गृहनगर नागपुर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं।

खिंडीपाड़ा में मरम्मत कार्य के दौरान मकान गिरने से दो की मौत...



भांडुप : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भांडुप पश्चिम के खिंडीपाड़ा में मरम्मत कार्य के दौरान मकान गिरने से दो युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय राजकुमार धोत्रे और 18 वर्षीय रामानंद यादव के रूप में हुई है। बीएमसी ने इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि घटना सुबह करीब 9.45 बजे हुई जब खिंडीपाड़ा इलाके में स्थित ढांचे में मरम्मत का काम चल रहा था। अधिकारी ने कहा कि राजकुमार धोत्रे (19) और रामानंद यादव (18) के रूप में पहचाने गए दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय निकाय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य किया।

आरोपी था जेल के अंदर! 20 साल से पुलिस ढूँढ़ रही थी बाहर, कोर्ट ने लगाई फटकार...



मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने 1999 के हत्या के एक मामले में छोटा शकील गिरोह के कथित शार्प शूटर का 20 साल तक पता नहीं लगा पाने के लिए शहर की पुलिस की आलोचना की है, जो इस अवधि के दौरान एक अन्य मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों के विशेष न्यायाधीश ए.एम.पाटिल ने 1999 में बॉम्बे अमन कमेटी के अध्यक्ष वाहिद अली खान की हत्या के आरोपी माहिर सिद्धीकी

को बरी करते हुए तीन फरवरी को परित अपने आदेश में यह टिप्पणी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मामले में कई विसंगतियों का हवाला दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिद्धीकी और एक सह-आरोपी ने जुलाई 1999 में मुंबई के एलटी मार्ग इलाके में खान के घर के पास कथित तौर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने मई 2019 में सिद्धीकी का पता लगाकर उसे

गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जांच के दौरान, पुलिस को सिद्धीकी और छोटा शकील समेत छह लोगों की सलिलता के बारे में पता चला। पुलिस ने कहा था कि उन्हें यह भी पता चला कि अपराध छोटा शकील के इशारे पर पक्ष में होगा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सिद्धीकी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल करते समय अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि वह घटना की तारीख से गिरफ्तारी तक फरार था। जबकि वह 2014 से 2019 के बीच एक अन्य मामले में विचाराधीन कैदी था और सीआईडी उसे गिरफ्तार कर चुकी थी। अदालत ने पूछा कि जब वह जेल में था तो पुलिस उसका पता लगाने में कैसे विफल रही। न्यायाधीश ने कहा, “पुलिस उसे खोजने में विफल रही, जबकि उसके पास फरार आरोपियों और विचाराधीन कैदियों का स्किर्ड होता है। इसकी असली वजह तो पुलिस ही बता सकती है।”

बुलढाणा में किसानों पर पुलिस का ‘लाठीचार्ज कांग्रेस नेता नाना पटोले ने की निंदा



मुंबई : कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक प्रदर्शन के दौरान किसानों पर ‘लाठीचार्ज’ करने का रविवार को बुलढाणा पुलिस पर आरोप लगाया और जिला पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की। पटोले ने यह भी मांग की कि शनिवार को हुई लाठीचार्ज की घटना की राज्य विधानमंडल की संयुक्त समिति द्वारा जांच करायी जाए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि किसान राज्य की ‘किसान-विरोधी एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार के सबक सिखायेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि शनिवार को जब किसान कपास और सोयाबीन के लिए उचित दाम और फसल बीमा से बंचत रहे थे, तब पुलिस ने उनपर ‘नृशंसता से लाठीचार्ज’ किया।

उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष राहुल भोजे और पूर्व मंत्री राजेंद्र शिंदे ने एक प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जा रहे थे, तब उन्हें पुलिस ने रोक दिया। पटोले ने कहा, “क्या अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक राज्य में अपराध है? लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी?